THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) No, Sir.

(b) and (c). At the intervention of the Government, an agreement has been reached between the spinners and weavers of staple fibre yarn for supply of 50% of the production of North India Mills to weavers in U. P., Punjab and Gujarat. The South India Mills Association have also voluntarily agreed to supply 100% of the production. The ceilling prices announced by the Manmade Fibre Spinners Association are applicable to supplies made to the decentralised sectors of both these zones within the agreed quota.

2. There has been no increase in prices in the supply of staple fibre yarns supplied to the weavers of these zones under the arrangements mentioned above in the post-war period. In the month of September 1971, there was a slight increase in prices, but this increase was outside the agreed percentage of supply quota. In the months of October, November and December, 1971, however, the prices shot up at high level, because of continuous strike in Gwalior Rayon Mills during these months.

राज्यों को अतिरिक्त बिजली की सप्लाई

1846. **डा० संकटा प्रसाद :**
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अतिरिक्त बिजली की माँग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बंजनाथ कुरील): (क) और (ख). गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में तारापुर, नासिक, ट्रांबे आदि जैसे विद्युत जनन यूनिटों के मजबूरन बन्द किये जाने के कारण विद्युत की अस्थायी कमी महसूस की जा रही है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन राज्यों में विद्युत की बढ़ती माँग पूरी करने में असमर्थ हैं क्योंकि इन राज्यों में विद्युत जनन पर्याप्त नहीं है। केन्द्र ने अन्त: सम्बदध महाराष्ट्र गुजरात विद्युत ग्रिड को मध्य प्रदेश और मैसूर से कुछ विद्युत की व्यवस्था कर दी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को कुछ हद तक राहत पहुँचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश और बिहार से भी और आंध्र प्रदेश के लिए मैसूर से कुछ विद्युत देने की व्यवस्था की गई है। भाखड़ा विद्युत केन्द्र से पंजाब और हरियाणा राज्यों को विद्युत की सप्लाई की अनुपूर्ति के लिए उत्तरी क्षेत्र के भाखड़ा ग्रिड को दिल्ली से ताप -विद्युत भी दी जा रही है। दीर्घावधिक कार्रवाई के तौर पर, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने 1972-73 की अवधि के लिए विद्युत विकास का एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें 17 7 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता परिकल्पित है जिसमे से निष्पादनाधीन परियोजनाओं से 8·5 मिलियन किलोवाट विकसित स्थलों पर विस्तार कार्यों से 5·5 मिलियन किलोवाट और अवधि के दौरान शुरू की जाने वाली नई स्कीमों से 3·7 मिलियन किलोवाट होगी। ऊपर के कार्यक्रम के कार्यान्वित हो जाने पर अनेक क्षेत्रों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के पर्याप्त मात्रा में पूरी हो जाने की आशा है।

Export of Leather Shoes

1847. SHRI K. MALLANNA :
SHRI N. SHIVAPPA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether some companies have been exporting leather shoes and chappals to foreign countries; and

(b) if so, the names of the Companies who were permitted by Government to export these items during the last two years and the amount of foreign exchange earned through such exports ?